केरल राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम

लिविशा व अन्य

मई 18, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय का टीजू, जे.जे.]

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885- धारा 10, 11, 12 और 16- मुआवजा- विद्युत लाइन खींचने के लिए पेड़ों की कटाई हेतु- का निर्धारण- अभिनिर्धारित किया गया: मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए क़ानून का उद्देश्य और प्रयोजन और उसके उद्देश्य के लिए उसमें निर्धारित कार्यप्रणाली मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए- इसके लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं हो सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा- विद्युत अधिनियम, 1910-धारा 51।

110 के.वी. विद्युत लाइन खींचने के लिए पेड़ों को काटकर हटा दिया गया था। बोर्ड/भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने मुआवजे की राशि निर्धारित की। संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे की राशि यह मानते हुए निर्धारित की कि वार्षिकी की गणना 5% रिटर्न के आधार पर की जाएगी।पुनरीक्षण

याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि और कटौती की दर 40% से बढ़ाकर 50% कर दी। इसलिए वर्तमान अपील की गई है।

अपील की अनुमति देना और मामले को उच्च न्यायालय को भेजना। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया:

1. भूमि के मूल्य को बढ़ाने और भूमि के मूल्य में कमी की दर को 40% से बढ़ाकर 50% करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण नहीं किया गया। ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया यह भी मामले के अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। मुआवज़े की राशि क़ानून के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी आवश्यक है। इसका कोई न कोई निश्चित फार्मूला नहीं हो सकता। हालाँकि, निस्संदेह निर्धारित फॉर्मूला, बोर्ड और/या संदर्भ न्यायालय को इसे लागू करने में सहायता कर सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है। अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन और उसके उद्देश्य के लिए उसमें निर्धारित कार्यप्रणाली मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए। [पैरा 7] [359-बी, सी, डी]

के.एस.ई. बोर्ड बनाम मार्थोमा रबर कंपनी लिमिटेड, (1981) केएलटी 646, संदर्भित।

2. भूमि की स्थिति, उस पर बिछाई गई हाई वोल्टेज बिजली लाइन के बीच की दूरी, उस पर लाइन की सीमा और यह तथ्य भी कि क्या हाई वोल्टेज लाइन भूमि के एक छोटे से ट्रैक के ऊपर से गुजरती है या जमीन के बीच से होकर गुजरती है और अन्य समान प्रासंगिक कारक मुआवजे के भुगतान के लिए निर्धारक होंगे। भूमि का मूल्य भी एक प्रासंगिक कारक होगा। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में भूमि का मालिक उस उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अपना वास्तविक अधिकार खो सकता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना था। जहां तक फल देने वाले पेड़ों के संबंध में मुआवजे का सवाल है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय को उसमें प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर मामले पर नये सिरे से विचार करना चाहिए।

[पैरा 10, 11 और 13] [361-जी-एच; 362-ए, बी, एफ]

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ए.पी. बनाम कमंदना रामकृष्ण राव और अन्य (2007) एआईआर एससीडब्ल्यू 1145; कपूर सिंह मिस्त्री बनाम वित्तीय आयोग और पंजाब सरकार के राजस्व सचिव और अन्य पंजाब सरकार के राजस्व सचिव और अन्य [1995] पूरक 2 एससीसी 635; हरियाणा राज्य बनाम गुरुचरण सिंह और अन्य, [1995] पूरक 2 एससीसी

637 और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम सत्यगोपाल रॉय और अन्य, [2002] 3 एससीसी 527, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 289/2006

सी.आर.पी. संख्या 1279/2003 मे केरल उच्च न्यायालय, एमाकुलम के दिनांक 28.3.2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

साथ

सी.ए. संख्या 2774,2773 2772,2771/2007

अपीलार्थी की ओर से एम. टी. जॉर्ज।

बेबी ऑगस्टीन, एबी ऑगस्टीन, एम.के. माइकल- प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का फैसला एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. विशेष अनुमति याचिका मे अनुमति दी गयी।

2. कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्नों से जुड़ी इन अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है। बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित और निगमित एक निकाय, केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा काटे और हटाए गए पेड़ों के लिए मुआवजे की राशि क्या होगी, इन अपीलों में एक प्रश्न शामिल

है। निर्विवाद रूप से, उक्त योजना के लिए मुआवजे की राशि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10, भाग III के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

3. इससे पहले कि हम उक्त प्रश्न पर विचार करें, हम अपीलार्थी बोर्ड और जिला न्यायाधीश होने के नाते संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि पर ध्यान दे सकते हैं।

4. 110 के.वी. विद्युत लाइन खींचने के लिए पेड़ों को काटकर हटा दिया गया है। बोर्ड/भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने मुआवजे की राशि निर्धारित की जिसके बाद संदर्भ दिया गया था। मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय विद्वान जिला न्यायाधीश ने कुंभा अम्मा बनाम केएसईबी, (2000) 1 केएलटी 542 में केरल उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन किया, जिसमें कहा गया कि वार्षिकी की गणना 5% रिटर्न के आधार पर की जाएगी। इसके विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन दायर किये गये हैं। उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, मुआवजे की राशि बढ़ा दी है, कमी की दर 40% के बजाय 50% तय की है।

5. इसमें कोई विवाद नहीं है कि केरल उच्च न्यायालय ने अलग-अलग समय पर इस मामले में अलग-अलग विचार रखे। आरंभ करने के लिए, केरल विद्युत बोर्ड बनाम थॉमस, (1961) केएलटी 238 में, यह माना

गया कि उक्त उद्देश्य के लिए जिस सिद्धांत का सहारा लिया जाना चाहिए वह वार्षिकी विधि है। मुआवजे की राशि की गणना के लिए प्रति वर्ष 5% ब्याज का उचित रिटर्न उचित माना गया। कथित तौर पर, बोर्ड मुआवजे की राशि निर्धारित करने में उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का पालन कर रहा था।

6. के.एस.ई. बोर्ड बनाम मार्थोमा रबर कंपनी लिमिटेड, (1981) केएलटी 646 में रिपोर्ट किए गए मामले में यह प्रश्न फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें उक्त न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राय दी कि 5 साल या 63 महीने की सामान्य अवधि, जो भी उचित हो और लंबी अवधि के आधार पर अपेक्षित रिटर्न हो, के लिए सावधि जमा पर रिटर्न का साधन अपनाना सुरक्षित होगा। प्रासंगिक समय पर बैंक की सामान्य ब्याज दर लंबी अवधि की जमा राशि, यानी 5 साल से अधिक, के लिए 10% थी। बोर्ड द्वारा उक्त ब्याज दर को उचित रिटर्न के रूप में अपनाया गया था और वार्षिकी की राशि की गणना उक्त आधार पर की जा रही थी। हालाँकि, कुंभा अम्मा (सुप्रा) में, उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि मुद्रास्फीति एक प्रासंगिक कारक है जिसे पेड़ों के विनाश के लिए मुआवजे की राशि की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. हालाँकि, हम देख सकते हैं कि आक्षेपित निर्णयों में से एक में, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया:

> "निचली अदालत ने भूमि का मूल्य रु. 20,000/-, प्रतिशत और कमी की दर 40% तय की है। प्रस्तुत प्रदर्शन A1 और A2 को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने भूमि का मूल्य 20,000/- रुपये तय करने का निर्णय सही है, जो इस मामले में उचित भूमि मूल्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस मामले में भूमि का मूल्य रु. 30,000/- प्रतिशत निर्धारित करता हूं। अतः भूमि के मूल्य में कमी की दर निचली अदालत द्वारा निर्धारित 40% के बजाय 50% तय की गई है। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया है।"

उपरोक्त दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है। अभिलेख में रखी गई सामग्री का विश्लेषण नहीं किया गया। ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया यह भी मामले के अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। मुआवज़े की राशि क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी आवश्यक है। इसका कोई न कोई निश्चित फार्मूला नहीं हो सकता। हालाँकि, निस्संदेह निर्धारित एक फॉर्मूला, बोर्ड और/या संदर्भ न्यायालय को इसे लागू करने में सहायता कर सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई सख्त

नियम नहीं हो सकता है। मुआवजे की राशि निर्धारित करने का एक निश्चित फॉर्मूला हालांकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी या संदर्भ न्यायालय का काम आसान बना सकता है लेकिन हमारी राय में प्रत्येक मामले को उसकी योग्यता के आधार पर लिया जाना आवश्यक है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन और उसके उद्देश्य के लिए उसमें निर्धारित कार्यप्रणाली मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय की 5 न्यायधीशों की बेंच ने बड़ी संख्या में ऐसे फैसलों का जिक्र किया जो मौत या घातक दुर्घटना के मामलों में लागू होते हैं। इसी दृष्टिकोण से 5 न्यायाधीशों की पीठ इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी कि 'ब्याज की वास्तविक दर' का क्या मतलब है। अंततः यह विचार करते हुए कि थॉमस (पूर्वोक्त) के मामले में 5% रिटर्न और के.एस.ई. बोर्ड (पूर्वोक्त) में देखी गई उच्च ब्याज दर नहीं, मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए, यह माना गया: -

> "इस मामले में विवाद तब पैदा हुआ जब याचिकाकर्ताओं की संपत्ति में खड़े पेड़ों को 9.9.1980 को काट दिया गया। उत्तरदाताओं ने हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है जिससे पता चले कि 1980 में ब्याज की वास्तविक दर 5% से कुछ अलग थी। 1981 केएलटी 646 पर आधारित उनका एकमात्र तर्क यह है कि जो प्रासंगिक है वह

ब्याज की प्रचलित दर है जो 10% थी। इस तर्क को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी दर मुद्रास्फीति के कारक को ध्यान में नहीं रखती है। इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में लागू होने वाली ब्याज दर 5% है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने आगामी अवधि के लिए वास्तविक ब्याज दर 5% निर्धारित कर दी है। एआईआर 1988 एपी 89 में जगन्नाध राव, जे. द्वारा भारत में लागू ब्याज दर को 4% माना गया है। उपरोक्त निर्णय के बाद 11 वर्ष बीत चुके हैं। क्या यह रिटर्न की वही दर होनी चाहिए जो उपरोक्त निर्णय से पहले और बाद की अवधि के लिए लागू की जानी चाहिए या उच्च या निम्न दर होनी चाहिए, यह उचित मामलों में तय किया जाने वाला मामला है जहां प्रासंगिक डेटा उपलब्ध है। ऐसे समय तक, बोर्ड रिटर्न की दर के रूप में 5% अपनाएगा। लेकिन, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि न्यायालय के निर्णयों से अंतिम रूप से समाप्त हुए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।"

8. भारत में टेलीग्राफ से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम बनाया गया था। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 51 इस प्रकार है:-

"51. कुछ मामलों में टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग। धारा 12 से 16 (दोनों सम्मिलित) और धारा 18 और 19 में निहित किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार, अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के मामले में, लिखित आदेश द्वारा, ऊर्जा के पारेषण के लिए विद्युत आपूर्ति-लाइनें, उपकरण और उपकरण लगाने या कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत जनता को ऊर्जा आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी भी सार्वजनिक अधिकारी, लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करना, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों (यदि कोई हो) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार लगाना उचित समझे, और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (3/1885) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के तहत टेलीग्राफ-प्राधिकरण के पास मौजूद कोई भी शक्ति, सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के

> प्रयोजनों के लिए टेलीग्राफ-लाइनें और पोस्ट रखने के संबंध में।"

9. तीसरे पक्ष की कृषि भूमि और/या अन्य संपत्तियों पर टेलीग्राफ लाइनें और विद्युत लाइनें दोनों खींची जानी आवश्यक हैं। ऐसी रेखाएँ खींचने में, पूरी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव उस संपत्ति के मूल्य में कमी होगा जिस पर ऐसी रेखा खींची गई है। टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 मुआवजे की राशि की गणना करने के तरीके का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 10 प्राधिकरण को किसी भी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ या उसके पार, या उसके अंदर या ऊपर एक टेलीग्राफ लाइन लगाने और बनाए रखने का अधिकार देती है। धारा 11 अधिकारियों को टेलीग्राफ लाइनों या पोस्टों की मरम्मत करने या हटाने के लिए संपत्ति में प्रवेश करने का अधिकार देती है। धारा 12 प्राधिकरण को उचित शर्तों के अधीन अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के खंड (सी) और (डी) के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी लाइनें बिछाने की अनुमति देने का अधिकार देती है, जैसा वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार है:-

> " 16. धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के मामले में मुआवजे के संबंध में विवाद-

(1) यदि धारा 10 के खंड (डी) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में धारा 10 में उल्लिखित शक्तियों के प्रयोग का विरोध किया जाता है या बाधित किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट, अपने विवेक से, आदेश दे सकता है कि टेलीग्राफ प्राधिकरण को उनका प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) यदि, धारा (1) के तहत आदेश देने के बाद, कोई व्यक्ति उन शक्तियों के प्रयोग का विरोध करता है, या संपत्ति पर नियंत्रण रखते हुए, उनके प्रयोग के लिए सभी सुविधाएं नहीं देता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (45/1860) की धारा 188 के तहत अपराध किया गया माना जाएगा।

(3) यदि धारा 10, खंड (डी) के तहत भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की पर्याप्तता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, यह, विवादित पक्षों में से किसी एक द्वारा उस उद्देश्य के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन करने पर, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) यदि मुआवज़ा प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के संबंध में, या उस अनुपात के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसमें इच्छुक व्यक्ति इसमें हिस्सा लेने के हकदार हैं, तो

टेलीग्राफ प्राधिकरण जिला न्यायाधीश की अदालत में उतनी राशि का भुगतान कर सकता है जितनी वह पर्याप्त समझे या, जहां सभी विवादित पक्षों ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि प्रस्तुत राशि पर्याप्त है या राशि उप-धारा (3) के तहत निर्धारित की गई है, वह राशि; और जिला न्यायाधीश, पक्षों को नोटिस देने और उनकी बात सुनने की इच्छा रखने के बाद, मुआवजा प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों या, जैसा भी मामला हो, उस अनुपात का निर्धारण करेगा जिसमें इच्छुक व्यक्ति हिस्सा पाने के हकदार हैं।

(5) उपधारा (3), या उपधारा (4) के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा विवाद का प्रत्येक निर्धारण अंतिम होगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसके तहत वह टेलीग्राफ प्राधिकारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी मुआवजे की संपूर्ण या आंशिक राशि, उन व्यक्तियों से वसूल कर सकता है, जिन्होंने उसे प्राप्त किया है।"

10. भूमि की स्थिति, उस पर बिछाई गई हाई वोल्टेज बिजली लाइन के बीच की दूरी, उस पर लाइन की सीमा और यह तथ्य भी कि क्या हाई वोल्टेज लाइन जमीन के एक छोटे से ट्रैक से गुजरती है या जमीन के बीच

से होकर गुजरती है और हमारी राय में अन्य समान प्रासंगिक कारक निर्धारक होंगे। भूमि का मूल्य भी एक प्रासंगिक कारक होगा। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में भूमि का मालिक उस उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अपना वास्तविक अधिकार खो सकता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना था।

11. जहां तक फल देने वाले पेड़ों के संबंध में मुआवजे का सवाल है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

12. संयोग से, हम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एपी बनाम कामन्दना रामकृष्ण राव और अन्य में इस न्यायालय के एक हालिया फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जो (2007) एआईआर एससीडब्ल्यू 1145 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए उपज के आधार पर दावे को प्रासंगिक माना गया है। इस सिद्धांत को दोहराया गया है- कपूर सिंह मिस्त्री बनाम वित्तीय आयोग और पंजाब सरकार के राजस्व सचिव और अन्य, [1995] पूरक 2 एससीसी 635, हरियाणा राज्य बनाम गुरचरण सिंह और अन्य, [1995] पूरक 2 एससीसी 637, पैरा 4, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम सत्यगोपाल रॉय और अन्य, [2002] 3 एससीसी 527। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (पूर्वोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> "14. इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के पास गुरुचरण सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पालन न करने और 8 साल के गुणक को लागू करके पेड़ों से उपज के आधार पर उत्तरदाताओं को देय मुआवजे का निर्धारण नहीं करने का कोई कारण नहीं था। इस मामले में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने 18 के गुणक को अपनाते हुए मुआवजा देने में स्पष्ट त्रुटि की है।"

13. इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को उसमें प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसलिए, आक्षेपित निर्णयों को कायम नहीं रखा जा सकता। इन्हें तदनुसार अलग रखा गया है। मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

के.के.टी. अपील की अनुमति दी जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी निखिल सिंह (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।